3. During 1992-93 only Rs. 10.00 crores have been provided so far.

4. In order to protect the interest of disadvantaged groups, adequate safeguards would be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, etc.

Water Problem of Rajasthan

4030. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware that as many as 4280 villages in Rajasthan are facing the problem of excessive fluoride and the quality of under-ground water in many districts has deteriorated;

(b) whether it is a fact that the State Government had sent a Project Report with an estimated cost of Rs. 688.21 crores which was also proposed to be posted to World Bank; and

(c) if so what action has been taken till date in this regard and if not in what manner Government propose to solve this water problem of Rajasthan ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The revised Project proposal covering 1597 villages with excessive fluoride in drinking water, 1000 villages with high salinity problem and 2000 villages with inadequate service level estimated to cost Rs. 400 crores has been forwarded to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) for seeking World Bank assistance.

Outcome of the South Asia Craft Meeting

4031. SHRI PRABHAKAR B. KORE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the recent South Asia Craft meeting organised in Delhi by South-South Solidarity and Dastakar representing Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh and Nepal; and

(b) if so, the outcome of the meeting ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKATSWAMY) : (a) Yes, Sir. Government are aware of the South Asia Craft Meeting held in Delhi.

(b) The Government have not received any recommendations in this regard.

मध्य प्रदेश में सड़कों के निर्माण में आ रही बाधाएं

4032. **श्री कैलाश नारायण सारंग :**
श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों से गुजरने वाली नई सड़कों के लिए वन विभाग द्वारा उस भूमि का हस्तांतरण न किए जाने से निर्माण कार्य में बाधाएं आ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी सड़कों के निर्माण में तेजी लाई जाए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई एच0 पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को राज्य के दस्युग्रस्त क्षेत्रों से गुजरने वाली अनुमोदित सड़कों के निर्माण के लिए निधियां स्वीकृत की हैं । अनुमोदित सड़कों का वास्तविक निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । पर्यावरण तथा वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि के अपवर्तन का अनुमोदन देने हेतु संबंधित मंत्रालय है । दस्युग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के प्रयोजन हेतु वन भूमि का अपवर्तन करने के लिए भारत सरकार के पास मध्य प्रदेश सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण

4033. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अपने विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और